RNI Number:
HPHIN/2019/78801

हिमाचल ग्रामीण

हिन्दी साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्या: L/SLN3000043621/2021-23

जन-जन की आवाज़

वर्ष 04 | अंक 16 | सोलन, बुधवार 08 फरवरी से 14 फरवरी 2023 | मूल्य एक रुपए

E-mail address: himachalgrameen@gmail.com

पृष्ठ तीन पर ▶ सलापड़ से तत्तापानी तक स्टीमर चलाने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में विधायकों से की बहुमूल्य सहयोग की अपील

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने में सभी विधायकों से अपने बहुमूल्य सुझाव एवं सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा में उन्होंने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में राज्य में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में जल्द ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी एक साल के भीतर सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केवल आवश्यकतानुसार ही डीजल चालित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर सीमित अनुमति प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेशभर में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए अभी तक 110 स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं जबकि लगभग 700 सरकारी भवनों में भी इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थल का चुनाव किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में भी चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा ताकि सार्वजनिक परिवहन में इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

विधायक प्राथमिकता बैठक में हिमाचल प्रदेश में नए दृष्टिकोण के साथ पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर तथा शाहपुर के विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्रमुखताएं भी गिनाईं।

धर्मशाला में हिमानी चामुण्डा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर तथा नगर के सौन्दर्यकरण के लिए सम्बन्धित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं।

नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों को इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलों एवं सिंचाई परियोजनाओं के निश्चित दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने जलशक्ति विभाग को खड्डों में बाढ़ प्रबन्धन के दृष्टिगत उचित स्थानों पर चेक डैम निर्मित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी से संबंधित चर्चा में कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी और इसके लिए निविदा होते ही कार्य पूरा करने की तिथि भी निश्चित कर ली जाएगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इन विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ ठोस एवं सार्थक कदम उठा रही है।

प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा तथा अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मज़बूत किया जा रहा है।

जीएसटी संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां कहा कि प्रदेश में जनवरी माह में 503 करोड़ जीएसटी संग्रह के साथ 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में जनवरी, 2023 तक जीएसटी संग्रह 4556 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के दौरान संग्रहित 3760 करोड़ रुपये के मुकाबले 21 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि करदाता अनुपालन में सुधार और मजबूती के साथ उसे लागू करने के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में यह वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा रिटर्न फाइलिंग में सुधार, रिटर्न की तेजी से जांच और जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने पर बल दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में जांच के दौरान 11 लाख ई–वे बिलों का सत्यापन किया है। विभाग हितधारकों के मुद्दों के समयबद्ध निवारण के साथ स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विभाग कर अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रहा है। विभाग ने पिछले छह महीनों में 400 से अधिक कर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

राज्य की सही आर्थिक सेहत के लिए सभी का सहयोग आवश्यक: सीएम

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठक में कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेगी, जिसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है।

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। विधायक प्राथमिकता की बैठक के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में जिला सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं के प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद योजना की यह पहली बैठक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेगी, जिसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव करेंगे तथा प्रमुख योजनाओं को बजट में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नई योजनाएं लाएं जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठकें विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव इन योजनाओं की निगरानी करते हैं और विधायक प्राथमिकता

की योजनाओं की प्रगति की जानकारी विधायकों को दी जाती है।

सोलन जिला

नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। उन्होंने रामशहर डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार नालागढ़–भरतगढ़, नालागढ़–बघेरी और काला अंब–पांवटा सड़क को फोरलेन बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने तथा क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया।

कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ट्रैफिक जाम की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन कंटोनमेंट क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रह रहे आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का मामला भी उठाया। विनोद सुल्तानपुरी ने कौशल्या नदी पर टिंबर ट्रेल के पास बांध और उस पर सड़क बनाने का भी आग्रह किया।

जिला बिलासपुर

झंडूता से विधायक जीत राम कटवाल ने जल संरक्षण से सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत करने, बेहतर सड़क सम्पर्क, पुलों के निर्माण और रोपवे बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जलक्रीड़ा स्थल विकसित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने वर्तमान सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने और हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों की सराहना की।

घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सतत् व नियोजित विकास के लिए दूरगामी योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने ग्रेविटी बेस्ड सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, श्रीनैना देवी और बाबा बालक नाथ जी मंदिर को गोविंद सागर झील पर रोपवे बनाकर जोड़ने का प्रस्ताव दिया।

बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट कंपनी विवाद का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने क्षेत्र के गांवों की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुचारू बनवाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कोल डैम तथा गोबिंद सागर से पीने के पानी की योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का आग्रह किया।

श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने श्रीनैना देवी मंदिर में विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने नैनादेवी में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण को गति प्रदान करने का आग्रह किया। ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा ओलिंडा से स्वारघाट से 66 करोड़ रुपये लागत की पानी की परियोजना का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आग्रह किया।

बैठक में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ बासु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन बना पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला विभाग

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। सत्ता संभालते ही हमने प्रण लिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे और हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमने जो कहा वो किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कथन आज पुनः चरितार्थ हुआ।

व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने आज रिज, शिमला से परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश व प्रदेश का पहला विभाग बन गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अन्य विभागों में भी शीघ्र ही परंपरागत ईंधन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में मानव का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा, जब हमारा पर्यावरण–हमारा परिवेश संरक्षित होगा। हम इस दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के सृजन की दिशा में भी दृढ़ता से कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के टोकन टैक्स में भी छूट दी गई है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए गंभीरता से कार्य किया गया है। इसके लिए लगभग 110 स्थानों तथा 700 सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के क्षेत्र में हिमाचल देश का मॉडल राज्य बनेगा। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश की परिवहन प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हरित ऊर्जा राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं।

05 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार होंगे अपडेट

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 05 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और उप–निदेशक उच्चतर शिक्षा को आदेश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार 05 और 15 वर्ष के छात्रों के आधार अपडेशन 07 और 17 वर्ष पर निर्योग्य (डिसेबल) हो जाएंगे।

केन्द्र सरकार का वार्षिक बजट मात्र छलावा: सुखविंदर सिंह सुक्खू

⊖बेरोजगारी व महंगाई से निपटने को बजट में प्रावधान नहीं

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत वार्षिक बजट 2023–24 निराशाजनक व आम जनता की आशाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और यह पूर्णतया निराशाजनक है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को आज भी केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों से पूर्व 'अच्छे दिनों' के वायदे के पूर्ण होने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार सृजन की दिशा में कोई भी प्रावधान नहीं है और शहरी रोजगार का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसानों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि के अलावा कुछ नहीं है। इससे केवल किसानों पर ऋण की देनदारी का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए खेती के उपकरणों और खाद में उपदान की कोई घोषणा नहीं है। इसके अलावा, मनरेगा में भी कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार को पूर्णतयः नजर अंदाज किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023–24 में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राज मार्गों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आयकर दरों में किया गया बदलाव पर्याप्त नहीं है तथा आम जनता को इससे और ज्यादा छूट की उम्मीद थी। यह बजट केवल समृद्ध लोगों के पक्ष में है और मंहगाई से परेशान मध्यम वर्ग को इससे बहुत निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे राज्यों के लिए बजट में कोई भी विशेष छूट नहीं है। हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार को पूर्व सरकार से 75 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इसके अलावा, कर्मचारियों और पैंशनरों की 11 हजार करोड़ रुपये की देनदारी भी बकाया है। उन्होंने कहा कि बजट में छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए जून, 2022 से समाप्त जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें थी और न ही बजट में किसी अन्य माध्यम से वित्त पोषण की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि वे हैरान है कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा नवम्बर माह में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, इस पर डब्बल इंजन सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लोगों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट मात्र पानी के बुलबुले के समान क्षण–भंगुर है।

सम्पादकीय

9 से 11 माह के 824 शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण

जिला सोलन के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचपन में होने वाली विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सके और उन्हें विभिन्न जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सके।

यह टीकाकरण अभियान रोटा वायरस संक्रमण, क्षय रोग (टी.बी), खसरा, काली खांसी, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी संक्रमण इत्यादि से रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है।

वर्तमान में जिले में लगभग एक हजार शिशुओं को टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए टीके लगाए जा रहे है। जिला में शिशु टीकाकरण अभियान के तहत 657 शिशुओं को विटामिन के. की खुराक दी जा रही है।

टीकाकरण अभियान के तहत जिला में क्षय रोग की रोकथाम के लिए 906 बच्चों को बैसिलस कैलमेट गुएरिन (बी.सी.जी) का टीका लगाया जा रहा है।

जिला में बच्चों को पांच घातक रोग जैसे गलघोंटू, काली खांसी, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (हिब) से बचाव के लिए 1016 बच्चों को पेंटावैलेंट की प्रथम खुराक, 1046 बच्चों को पेंटावैलेंट की दूसरी खुराक तथा 996 बच्चों को पेंटावैलेंट की तीसरी खुराक दी जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला सोलन को पोलियो मुक्त बनाने के 691 नवजात शिशुओं को ओ.पी.वी. की खुराक, 1016 शिशुओं को ओ.पी.वी 1 की खुराक, 1046 शिशुओं को ओ.पी.वी. 2 की खुराक तथा 996 बच्चों को ओ.पी.वी 3 की खुराक दी जा चुकी है। अब तक 767 बच्चों को ओ.पी.वी की बूस्टर डोज भी दी गई है।

जिला सोलन में 1016 बच्चों को निष्क्रिय पोलियो वायरस (आई.पी.वी 1) तथा 996 बच्चों को आई.पी.वी 2 के टीके लगाए जा चुके है।

जिला सोलन में हेपेटाइटिस बी रोग से बचाव के लिए 664 नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जा चुके है।

जिला में रोटावायर संक्रमण की रोकथाम के लिए 1016 बच्चों को रोटावायरस की प्रथम खुराक, 1046 बच्चों को दूसरी तथा 996 बच्चों को रोटावायरस की तीसरी खुराक दी जा चुकी है। जिला के शिशुओं को न्यूमोनिया से सुरक्षा के लिए 989 बच्चों को पी.सी.वी का प्रथम टीका, 986 बच्चों को पी.सी.वी का दूसरा टीका तथा 811 बच्चों को पी.सी.वी की बूस्टर डोज दिया जा चुकी है।

जिला सोलन में खसरा के संक्रमण से बचाव के लिए 9 से 11 माह तक की आयु वर्ग के 284 शिशुओं को मीजल्स रूबेला का प्रथम टीका लगाया जा चुका है, जबकि 16 से 24 माह की आयु वर्ग के 767 बच्चों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है।

जिला सोलन में अब तक 9 से 11 माह के 824 शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है जिसमें 441 बाल तथा 383 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के पांच वर्ष की आयु से अधिक के 1418 बच्चों को डिप्थीरिया–टेटनस–पर्टुसिस (डी.पी.टी.) के टीके डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से बचाव के लिए दिए जा चुके है।

इसके अतिरिक्त, 10 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के 1447 बच्चों को शरीर को संक्रमणकारी कीटाणुओं तथा टेटनस रोग की रोकथाम के लिए टेटनस टॉकसाइड (टी.टी.10) व टेटनस डिप्थीरिया (टी.डी 10) के टीके भी लगाए जा चुके है। जिला सोलन में 16 वर्ष से अधिक आयु के 634 बच्चों को टी.टी 16 व टी.डी 16 के टीके लगाए जा चुके है।

जिला सोलन में टीकाकरण अभियान को सुदृढ़ करने हेतु यूविन पोर्टल का सफलता पूर्वक क्रियान्वन भी किया जा रहा है। हाल ही में आरंभ किया गए यूविन पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला सोलन में आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जच्चा व बच्चा के टीकाकरण की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। इसका लाभ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाले टीकों के लिए होगा। पोर्टल के माध्यम से क्षेत्र में टीकाकरण लग रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला से ग्रीन मोबिलिटी अभियान के तहत व पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है, जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के बाद अब राज्य सरकार अन्य विभागों की परंपरागत ईंधन वाहनों को भी एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रतिस्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न विभागों के खर्चों में काफी कमी आयेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को साफ–सुथरा रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 'परवाणू–नालागढ़–ऊना–हमीरपुर–नादौन–देहरा' परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कोरिडोर बनाने जा रही है। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई–बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रामपुर–शिमला कोरिडोर में भी अधिकांश ई–बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला लोकल डिपो को पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा तथा नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई–बसें शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपये की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक ई–बसें शामिल की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परंपरागत ईंधन वाले वाहनों से उड़ने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, इसलिए देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी है और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के परिवहन साधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता और अपरिहार्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 अधिसूचित की है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन साधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, हिमाचल को इलेक्ट्रिक परिवहन व इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के हब के रूप में विकसित करना है। इसके साथ–साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश भर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना तथा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सबसिडी तथा अन्य प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स में भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को गति देने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी वायदों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारी तथा पैंशनरों के देय एरियर को भी देने के लिए वचनबद्ध है।

इस अवसर पर उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान में परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान कर एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इन वाहनों को खरीदने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस नई पहल से जहां पैसे की बचत होगी, वहीं पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए भी एक सार्थक कदम है, जो वर्तमान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।

उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 50 दिन के कार्यकाल में तीन ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं, जिनमें ओ.पी.एस., इलेक्ट्रिक वाहन तथा अनाथ बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुख–आश्रय सहायता कोष शामिल हैं। वर्तमान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

प्रधान सचिव, परिवहन आर. डी. नजीम ने मुख्यमंत्री स्वागत किया तथा परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, रामकुमार चौधरी तथा किशोरी लाल, विधायक विनय कुमार, नंद लाल, इन्द्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, हरीश जनारथा, मलेंदर राजन तथा सुदर्शन बबलू और पूर्व मंत्री आशा कुमारी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

प्रदेश सरकार का बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा : मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक योजना 2023–24 के लिए ऊना, हमीरपुर, कुल्लू तथा सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में विचार–विमर्श और परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, जिसमें विपक्ष का सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे कम करने होंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार का आने वाला बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा जिस पर सरकार की योजनाएं लक्षित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वार्षिक योजना 2023–24 का आकार 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर की अधिसूचना के लिए 7 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न करें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 962 करोड़ के बजट का परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें। उन्होंने विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बनाने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए एफसीए, एफआर और गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

इससे पूर्व वित्त सचिव अक्षय सूद ने मुख्यमंत्री, मंत्रिगण व विधायकगण का बैठक में स्वागत किया।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य सचिव व संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, योजना सलाहकार वासू सूद और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीमार महिला को लाहौल से एयर लिफ्ट किया गया

सुख की सरकार के मानवीय दृष्टिकोण की घाटी के लोगों ने की सराहना

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के माध्यम से आज सूचना प्राप्त हुई कि जिला लाहौल–स्पिति के उदयपुर उपमंडल के गांव छालिंग निवासी पदमा देचिन गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता है। यह जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री ने पदमा देचिन को हेलिकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।

प्रशासन ने बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की। अब पदमा देचिन का कुल्लू अस्पताल उपचार किया जा रहा है। भारी बर्फबारी से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पदमा देचिन का उपचार घाटी में संभव नहीं हो पा रहा था और उन्हें इसके लिए कुल्लू स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च अधिमान देते हुए पदमा देचिन का उपचार करवाने के लिए प्रशासन को तुरंत हेलिकॉप्टर का प्रबंध कर उन्हें कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। यह सुख की सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री जरूरतमंदों और विपरीत परिस्थितियों से घिरे प्रदेशवासियों के लिए चिंतित रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में फंसे किसी भी प्रदेशवासी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्वरित निर्णय लेकर उसका समाधान सुनिश्चित करते हैं।

प्रथम बार निर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री से की भेंट

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित विधायकों की कार्यकारिणी ने अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मामलों पर अनौपचारिक चर्चा भी की।

गत दिनों शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया को प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित विधायकों की कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया है। उनका अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर की ओर से प्रस्तुत किया गया था। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज और शिमला (शहरी) के विधायक हरीश जनारथा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

कार्यकारिणी में महासचिव पद की जिम्मेदारी बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल को सौंपी गई है। उनके नाम का प्रस्ताव चंबा के विधायक नीरज नय्यर व इंदौरा के विधायक मलिंद्र राजन ने किया।

गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ आईटी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी करसोग के विधायक दीप राज को सौंपी गई है।

इस दौरान सभी विधायकों ने उनके समक्ष पेश आने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया। विधायक किस प्रकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, इस पर भी चर्चा की गई।

माल भाड़े की दरों को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। माल भाड़े की दरों को लेकर सीमेंट कम्पनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच जारी विवाद को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ आज देर शाम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिलासपुर जिले से सम्बन्धित विधायकों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि यह गतिरोध सर्वमान्य हल से दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि फैक्टरी में कार्य शुरू होना चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों सहित वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आज की बैठक में सभी यूनियनों की ओर से प्रस्तावित भाड़े की दरों पर फैक्टरी प्रबन्धन से चर्चा करेगी। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दो दिनों के भीतर फैक्टरी प्रबन्धन से वार्ता करने के निर्देश दिए।

ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने विवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूनियनों की ओर से सरकार को हर संभव सहयोग जारी रखा जाएगा। बैठक में बी.डी.टी.एस. बरमाणा, सोलन जिला ट्रक ऑपरेटर, बाघल लैंडहोल्डर्स, गोल्डन लैंड लूजर, अंबुजा दाड़ला कसलोग मांगू, कूरगन लैंड लूजर तथा माइनिंग लैंड लूजर के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायकगण इंद्र दत्त लखनपाल, राजेश धर्माणी, रणधीर शर्मा, जे.आर.कटवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति तथा निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन से संत बाबा नाहर सिंह जी की स्मृति में राज्य रेडक्रॉस समिति को ऑल इंडिया एक्यूपंक्चर फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा दान की गई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पीड़ित मानवता की सेवा में ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने एएनआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एएनआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुरिंदर कपूर (70) के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनका शनिवार को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से पैदा हुई रिक्तता को भरना मुश्किल है।

सुरिंदर कपूर लंबे समय से एएनआई से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस मीडिया हाउस को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुःख की घड़ी में अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रदेश सरकार प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। हिमाचल में सुख की सरकार मानवीय सरोकारों को विशेष अधिमान देते हुए सेवा और सुशासन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के दो माह के भीतर ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेक पहल कर बेसहारा व ज़रूरतमंद लोगों को सहारा प्रदान किया है। नववर्ष की पावन वेला पर मुख्यमंत्री सुख–आश्रय सहायता कोष की स्थापना से ही यह स्पष्ट हो गया था कि जन कल्याण की दिशा में वह मज़बूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की पहल से सुख–आश्रय सहायता कोष के माध्यम से अब अनेक लोगों की जिंदगी संवरने लगी है।

बुधवार को शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, न ही वह अनाथ आश्रम में रह सकती हैं क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब यह बालिका एक वर्ष तक अनाथालय में रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस बालिका को घर बनाने के लिए भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के भीतर उसका अपना आशियाना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान करेगी। यह मुख्यमंत्री के दृढ़ इरादों और

मुख्यमंत्री ने कोल डैम में सलापड़ से तत्तापानी तक स्टीमर चलाने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए

▶▶विधायक प्राथमिकता बैठक में विकासात्मक कार्यों पर चर्चा

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। शिमला में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान करसोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपराज कपूर ने क्षेत्र में सड़कों, शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय व मृदा परीक्षण केंद्र खोलने और करसोग से दिल्ली के लिए वोल्वो बस चलाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का प्रावधान करने का भी आग्रह किया।

सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने निहरी पुलिस चौकी को थाने में स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने सुंदरनगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा वाटर ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत शुरू करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कोल डैम में सलापड़ से तत्तापानी तक स्टीमर चलाने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से भारतमाला प्रोजेक्ट में पुंघ तलेली डैहर सड़क को स्वीकृत करवाने का आग्रह भी किया।

नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि उनके क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। उन्होंने ज्यूणी खड्ड में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने बफर स्टोरेज टैंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने डिग्री कॉलेज बासा के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का भी आग्रह किया।

द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने ऊहल व ब्यास नदी पर जलविद्युत परियोजना लगाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धन का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि भुभु जोत टनल बनने से मंडी और कुल्लू जिला आपस में जुड़ेंगे और कांगड़ा से मंडी होते हुए कुल्लू तक जाने के लिए पर्यटकों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रकाश राणा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने भारी बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को जल्द खोलने, स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने और जल शक्ति विभाग की योजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने विपक्ष की ओर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।धर्मपुर से विधायक चंद्र शेखर ने किसानों की सुविधा के लिए खेतों की बाड़बंदी पर बल देते हुए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकाघाट में पीपीपी मोड पर बस स्टैंड बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों को 120 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित करने की बात की। उन्होंने पपलोग ड्राइविंग स्कूल के बेहतर उपयोग और सैनिक अकादमी खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और एंबुलेंस सुविधा को सुदृढ़ करने आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने धर्मपुर और संधोल को नगर परिषद बनाने तथा कमलाह में रोपवे प्रोजेक्ट लाने का प्रस्ताव किया।

इसके उपरांत सरकाघाट, मंडी और बल्ह क्षेत्र के विधायकों ने भी अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए विभिन्न प्रस्ताव दिए।

मुख्यमंत्री के आगमन पर हमीरपुर में नजर आया उत्सवी माहौल

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। आज दोपहर लगभग डेढ़ बजे जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर स्थित गांधी चौक पहुंचे, पूरा शहर हर्ष और करतल ध्वनि से गूंज उठा। लोगों ने उत्साह के साथ पुष्पवर्षा की और फूल मालाओं से अपने प्रिय नेता का स्वागत किया।

शनिवार को दिन भर हमीरपुर उत्सवी माहौल से सराबोर रहा। हर आयु वर्ग के लोग मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए उत्सुक दिखे।

भोरंज विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा गाजियां से आए पंकज कुमार ने कहा कि शुक्रवार सायं से ही वह मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए आतुर थे। आज सुबह 10 बजे घर से चले और 11 बजे से गांधी चौक, हमीरपुर में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री का शानदार व्यक्तित्व है और लोगों से सीधे जुड़ कर संवाद करते हैं। वहीं ताल निवासी निशांत कुमार ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही प्रदेश के युवाओं में विशेष उत्साह है। मुख्यमंत्री अनाथ बच्चों, एकल महिलाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को उनमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। युवाओं के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीवन प्रेरणास्रोत है उन्होंने लंबा संघर्ष किया और आज राज्य के सबसे बड़े पद पर विराजमान हैं।

भूम्पल से आई निशा कटोच ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए संघर्ष की मिसाल हैं। वह प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए दूरदर्शी सोच रखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू करने का प्रदेश सरकार का निर्णय पूरे देश में एक क्रांतिकारी कदम है। यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच को दर्शाता है, यह व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध होगा। इससे पहले, हैलीपैड से लेकर गांधी चौक तक स्थानीय निवासी जगह–जगह मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े रहे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी का अभिवादन स्नेहपूर्वक स्वीकार किया।

गंभीर बीमारी से ग्रसित 18 वर्षीय युवती के उपचार का खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। हमीरपुर जिला के बिझड़ी क्षेत्र से संबंध रखने वाली 18 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। मीनाक्षी ठाकुर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में इस संबंध में प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

मीनाक्षी ठाकुर ने आज अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सर्किट हाउस हमीरपुर में भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। मीनाक्षी ने बताया कि उसका परिवार इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन को मीनाक्षी की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी के इलाज के लिए जो भी व्यय होगा, वह प्रदेश सरकार वहन करेगी। मानवीय संवेदनाओं के साथ सामाजिक सरोकार को मुख्यमंत्री सर्वोच्च अधिमान देते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज के वंचित वर्ग के लिए अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए हैं। वह निरंतर ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को संबल प्रदान कर सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार का प्रमुख ध्येय : मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला में आगमन पर हमीरपुर में उमड़े जन सैलाब ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर हमीरपुर जिला और अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में हर्षध्वनि से नारेबाजी और पुष्प वर्षा की।

हमीरपुर के गांधी चौक में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपार जन समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस एवं सार्थक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विश्व स्तरीय तकनीक युक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के पूर्ण होने के उपरांत लोगों को उपचार के लिए एम्स, टांडा, आईजीएमसी तथा अन्य निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा हमीरपुर में नया बस स्टैंड निर्मित करने के लिए बजट में धन का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इनडोर स्टेडियम खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गसोता महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और ताल में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है तथा अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की मांग को पूरा

हमीरपुर आगमन पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत

मुख्यमंत्री ने गसोता महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की

करते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो कहा, वह पूरा किया है। प्रदेश सरकार अपने सभी वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोग उनका परिवार है। प्रदेश सरकार हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन–रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि वह 40 वर्षों से भी अधिक समय से जन सेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों के सुख–दुःख से भली–भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के पहले दिन से ही वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आयु बढ़ाकर 27 वर्ष कर दी है और उन्हें घर बनाने के लिए चार बिस्वा जमीन भी दी जाएगी। साथ ही सरकार उनकी उच्च शिक्षा का खर्च भी उठाएगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा–सुमन अर्पित किए।

हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया और उन्हें स्मृति–चिन्ह भेंट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता सरकार के साथ है।

विधानसभा क्षेत्र भोरंज से विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के विकास के लिए उम्मीद की नई किरण हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष व जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

बड़सर विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीवन संघर्ष और जन–सेवा की मिसाल है। मुख्यमंत्री आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनीता वर्मा, मंजीत डोगरा, कांग्रेस नेता प्रेम कौशल, पुष्पिंदर वर्मा, राजेंद्र जार, उपायुक्त देवश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा, संगठन के पदाधिकारी और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से किया जाए निपटान : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मीडिया में प्रकाशित समाचारों व पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बोर्ड के संज्ञान में आया है कि राज्य में 70 डंपिंग स्थलों पर प्लास्टिक कचरा बेतरतीब ढंग से फेंका गया है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 फरवरी, 2023 को शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को बेतरतीब ढंग से डंप किए गए प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 में उत्पादित ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान और पुराने अपशिष्ट स्थलों के उपचार के संबंध में स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि वर्तमान में धर्मशाला, मंडी, बद्दी, सोलन, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, ऊना, संतोखगढ़, बैजनाथ, चुवाड़ी, डलहौजी, रिवालसर, सरकाघाट और हमीरपुर शहरी स्थानीय निकायों में 1,90,796 टन अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शहरी निकायों में अपशिष्ट उपचार कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

मुकेश अग्निहोत्री ने संत बाबा बाल जी का लिया आशीर्वाद

ऊना, हिमाचल ग्रामीण। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के सुप्रसिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां में राष्ट्रीय संत बाबा बालजी के सानिध्य में 1 से 13 फरवरी तक चल रहे श्रीमद्भागवत गीता प्रवचन में पहुंचकर संत बाबा बाल जी का आशीर्वाद लिया तथा भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि वह संत बाबा बाल जी के आभारी हैं जिन्होंने इस विशाल आध्यात्मिक समारोह में आने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि संत बाबा बाल उत्तर भारत के बड़े संतों में शुमार हैं और लोगों की भी इस पवित्र स्थल से गहरी आस्था है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर प्रवचन सुनते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि संत बाबा बाल जी से ऊना जिला के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। यह आश्रम उत्तर भारत के श्रद्धालुओं की गहन आस्था का केंद्र है तथा ऊना जिला के लिए यह हर्ष व गौरव का विषय है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों के विकास एवं सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम माता श्री चिंतपूर्णी जी में श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। चिंतपूर्णी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हवन, प्रसाद, लंगर व जागरण इत्यादि की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि मंदिर स्थल पर पहुंचने के पश्चात उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

केंद्रीय बजट दिशाहीन एवं रोजगार विरोधी : नरेश चौहान

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए प्रस्तुत बजट को दिशाहीन एवं रोजगार विरोधी बजट करार दिया है। आज यहां प्रेस को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष को देखते हुए केन्द्र सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगारपरक नीति की घोषणा होती लेकिन इस बजट ने हर वर्ग को निराश किया है।

मीडिया सलाहकार ने कहा कि वास्तव में महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त है और बजट में इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमतों में ठहराव आया है। महिलाओं के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं हैं। किसानों, बागवानों तथा आम आदमी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स दरों में भी लोगों को उलझाने का प्रयास किया गया है जबकि बचत को प्रोत्साहित करने की बजाय खर्चों को बढ़ा दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है और पिछली सरकारों का 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है जिसमें से पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा ही 30 हजार करोड़ का कर्ज है। सरकार के पास करोड़ों रुपये की देनदारियां हैं। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को छठे वेतन आयोग के बकाया की करोड़ों रुपये की राशि देय है और इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से हिमाचल को 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल को निराश किया गया है।

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का होगा उपयोग : मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में प्रदेश में सभी पेयजल योजनाओं में फिल्टर तथा यूवी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा।

शिमला में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान नाहन से विधायक अजय सोलंकी द्वारा उठाए गए एक मामले पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सभी पेयजल योजनाओं में जल की गुणवत्ता संबंधी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल की आपूर्ति से जलजनित रोगों के फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने विभाग को जलापूर्ति पाइपों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने और इनमें गंदगी इत्यादि न पनप सके, इसके लिए पुख्ता उपाय करने के भी निर्देश दिए।

विधायक प्राथमिकता बैठक में आगामी पांच वर्षों में हिमाचल की प्रगति के प्रति प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की सोच की परिलक्षित हुई। उन्होंने आनी के विधायक की ओर से उठाए गए मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब हिमाचल को फल राज्य के बाद दुग्ध उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि

विधायक प्राथमिकता बैठक में हिमाचल की प्रगति के प्रति मुख्यमंत्री की सोच हुई परिलक्षित

आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे विशेष तौर पर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से प्रदेश में सड़क परियोजनाओं से हटकर रोपवे तथा सुरंगों इत्यादि के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस बारे में प्रस्ताव लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हिमाचल में इस पर निकट भविष्य में काफी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत विधायक सुरंग निर्माण तथा रोपवे इत्यादि की संभावनाएं तलाशते हुए इसके लिए प्रस्ताव लाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य के अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए भी विधायक प्रस्ताव लाएं तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों में बेतरतीब निर्माण पर उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के परिवेश के अनुसार भवनों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए वन स्वीकृतियों एवं अन्य आपत्तियों इत्यादि के निपटारे के लिए समयसीमा तय की गई है। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों से संबंधित सभी मामलों की सूची उपलब्ध करवाएं ताकि उच्चतम स्तर पर विचार विमर्श कर इनका सर्वमान्य हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर ऐसे मामलों की निरंतर निगरानी की जा रही है।

विधायक प्राथमिकता बैठक के प्रथम दिवस मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता, धैर्य से सबकी बात सुनने तथा उपयोगी सुझावों पर उचित निर्णय लेते हुए प्रशासनिक अमले को तत्काल निर्देश जारी करने की उनकी शासकीय दक्षता की सभी विधायकों ने खुले मन से प्रशंसा भी की।

सीएम ने जिला ऊना तथा हमीरपुर के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक योजना 2023–24 के लिए ऊना तथा हमीरपुर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में विधानसभा क्षेत्र गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि मुबारकपुर में मल निकासी योजना की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से 50 मिनी ट्यूबवैल लगाने का आग्रह किया। उन्होंने चार सड़कों और दो फ्लाइओवर बनाने का प्रस्ताव भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए दो स्थलों का चयन कर लिया गया है।

ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने एएंडईएस मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने एएंडईएस को समयबद्ध करने के निर्देश दिए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना के लिए बाईपास की भी आवश्यकता है।

कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सब जज न्यायालय खोलने का आग्रह किया और कहा कि इसके लिए भवन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं है और यहां एक अच्छा खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है।

हमीरपुर जिला

भोरंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश कुमार ने क्षेत्र के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि विधायक 150 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं और यह सीमा पूर्ण हो चुकी हैं, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उनके क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से कम पैसा खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए सात सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, लेकिन नाबार्ड से धनराशि स्वीकृत होकर नहीं आ रही है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में टाउन हॉल का निर्माण कार्य छह साल से लम्बित है और 75 लाख रुपये व्यय नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा। राजेंद्र राणा ने सिविल अस्पताल सुजानपुर की क्षमता 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर करने का प्रस्ताव भी किया।

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा ने ताल में वेटनरी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि इसके लिए पशु पालन विभाग के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने झगड़याणी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला तथा अणु को मल निकासी योजना से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने हमीरपुर में शहीद स्मारक बनाने और नए बस अड्डे का प्रस्ताव भी किया।

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने बड़सर में बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने भवनों के रखरखाव, विशेष रूप से स्कूलों के भवनों के लिए धनराशि का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी, 2023 तक प्रदेश के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था व स्कूलों के भवन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग की योजनाओं में मुरम्मत के लिए धन का प्रावधान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने, नई पार्किंग के निर्माण और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टाउन हॉल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विधायक भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तुत करें अपनी योजनाएं : मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। विधायक प्राथमकिता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की प्राथमिकताएं बजट की दिशा तय करती हैं, ऐसे में सभी विधायक अपनी योजनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तावित करें और सरकार का सुशासन प्रदान करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं और योजनाओं के साथ–साथ अन्य सुझाव भी दें, सरकार उन पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार इस दिशा में कड़े निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं की समय सीमा तय कर उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मद्द मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से पानी की योजनाऐं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करें और अगर पानी की योजना व स्रोत को नुकसान पहुंचता है तो इस पर एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान किया जाए।

कांगड़ा

विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्र में युवाओं को नशे से बचाने के लिए दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल की तीन योजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया।

विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने क्षेत्र में ड्रग्स और अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने का आग्रह किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने शाहनहर से छूटे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वितरण प्रणाली का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया।

जसवां–प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने एफसीए और एफआरए स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और प्रक्रिया को समयबद्ध किया जा रहा है, जिसके लिए यूजर एजेंसी, डीएफओ और संबंधित जिलों के उपायुक्तों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

फतेहपुर के विधायक भवानी सिह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ–साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अधिक रोजगार सृजित करने तथा नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।

विधानसभा क्षेत्र ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया, ताकि इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके। उन्होंने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मण्डल खोलने का प्रस्ताव किया। उन्होंने 51 पंचायतों के लिए सुराली में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया। विधायक ने मझीण, लगडु और खुंडिया में बस स्टैंड और टीहरी में बहुतकनीकी महाविद्यालय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एडीबी की सहायता से ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।

जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में एचआरटीसी डिपो की आवश्यकता है और उसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए।

विधानसभा क्षेत्र सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ट्रक यूनियन व सीमेंट कंपनी के बीच गतिरोध का सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा समाधान : मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। माल ढुलाई भाड़े को लेकर सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच विवाद को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दाड़लाघाट ट्रक ऑपरेटर यूनियन तथा एसीसी बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को एक बैठक हुई। बैठक में सीमेंट कंपनी तथा ट्रक ऑपरेटर के बीच मालभाड़े को लेकर चल रहे विवाद को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने सीमेंट कंपनी के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर अपना प्रस्ताव प्रदेश सरकार के समक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है।

कुल्लू तथा सिरमौर जिला की विधायक प्राथमिकता बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि क्षेत्र के मुख्य पर्यटन स्थलों में पार्किंग की उचित व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। इससे न केवल यातायात के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म आधारित पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बंजार में पुलिस का ट्रैफिक विंग स्थापित किया जाना चाहिए।

आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने रघोपुर गढ़ के लिए रास्ते के निर्माण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि बाघा सराहन–बठाड़ में टनल बनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने किसानों के लिए दूध की दरों से संबंधित मामला भी उठाया।

इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है।

सिरमौर जिला

पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने चूड़धार के लिए रोपवे निर्माण तथा शिरगुल मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा संपर्क सुविधाओं को सशक्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण का कार्य अति शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नाहन में पार्किंग निर्माण और सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने भूमिहीन लोगों को दो–तीन बिस्वा योजना के तहत भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में नशे और अवैध खनन पर चिंता व्यक्त की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इसके दृष्टिगत गंभीरता से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है।

रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय कुमार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नौहराधार या हरिपुरधार से रोपवे बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेणुका जी झील में गाद भरने का मामला भी उठाया। उन्होंने रेणुका डैम परियोजना में वन विभाग की स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने तथा विस्थापितों की समस्या को सुलझाने का आग्रह भी किया।

पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय पुल निर्माणाधीन है। हिमाचल प्रदेश की ओर इस पुल तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने इसके दृष्टिगत प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने पांवटा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या सुलझाने के लिए नए सब स्टेशन निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह भी किया।

मल निकासी संयंत्रों में तय मापदंडों का अनुपालन करने के निर्देश दिए

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आज यहां कहा कि बोर्ड ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एस.जे.पी.एन.एल) और जल शक्ति विभाग द्वारा मल उपचार संयंत्रों (एस.टी.पी.) में तय मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करने से जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार बद्दी के समीप सिरसा नदी, मारकण्डा नदी, ब्यास नदी, अश्वनी खड्ड, गिरी नदी और पब्बर नदी के प्रदूषित भागों का कायाकल्प करने के लिए वर्ष 2019–20 में कार्य योजना तैयार की गई थी। एस.जे.पी.एन.एल. और जल शक्ति विभाग को एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता थी।

जल शक्ति विभाग राज्य के मुख्य शहरी क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में 99.97 एमएलडी क्षमता के 70 एस.टी.पी. का संचालन कर रहा है। इसके अलावा एस.जे.पी.एन.एल. के पास 26.06 एमएलडी क्षमता के 06 एसटीपी हैं, जिन्हें स्तरोन्नत करने की आवश्यकता है। हालांकि, अश्वनी खड्ड के प्रदूषित नदी खंड का कायाकल्प नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। प्रदूषकों की सघनता को कम करने के लिए अश्विनी खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र की जैव उपचारात्मक प्रक्रिया को भी तेज करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड नियमित रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का निरीक्षण, निगरानी और सैंपल भी एकत्रित कर आवश्यकता पड़ने पर नियामक कार्रवाई करता है।

संजय गुप्ता ने कहा कि इन गैर–अनुपालन वाले एस.टी.पी. के अनुचित संचालन और कामकाज के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर संशोधन, उन्नयन, विस्तार और निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझावों का स्वागत : सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज विधायक प्राथमिकता बैठकों के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल–स्पिति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा व हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। उन्होंने एक बार पुनः दोहराया कि वह सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इसके लिए सभी के सुझावों का स्वागत है, ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे।

बैठक मे चर्चा के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनजातीय और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साल भर पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए जल शक्ति विभाग को एंटी फ्रीज पाइपें बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी फ्रीज पाइप के साथ–साथ चैंबर बॉक्स व टैंक बनाकर वर्ष भर पानी की सुविधा देने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की आधुनिक तकनीक का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही है।

चंबा जिला

विधानसभा क्षेत्र चुराह के विधायक हंसराज ने विपक्ष की ओर से सरकार को सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए अपने क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, चंबा मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने चंबा को हेली टैक्सी के साथ जोड़ने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। हंसराज ने जिला चंबा में अनछुए स्थलों को पर्यटकों के लिए विकसित करने तथा साच पास में रोपवे लगाने का प्रस्ताव किया।

भरमौर से विधायक डॉ. जनक राज ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ का आग्रह किया। उन्होंने पांगी घाटी में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप 5–5 मेगावाट के दो विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया। विधायक ने होली–उतराला मार्ग निर्माण का प्रस्ताव करते हुए कहा कि यह सड़क चंबा जिला की भाग्य रेखा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने इस मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पुनः बनाने के निर्देश दिए।

चंबा से विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचा मजबूत करने तथा रिक्त पद भरने का आग्रह किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 8 करोड़ की पेयजल योजना बनाने के साथ–साथ शहर में पार्किंग और मिनी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव किया।

डलहौजी से विधायक डी.एस. ठाकुर ने सलूणी अस्पताल के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने, डलहौजी को स्मार्ट सिटी में शामिल करने तथा नए बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने एफआरए और एफसीए मामलों को स्वीकृत करने में तेजी लाने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक ने डलहौजी और खज्जियार को रोपवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी किया।

जिला शिमला

चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने कुपवी अस्पताल के नए भवन के लिए धन का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं के लिए बजट प्रदान करने, सराहान से चूड़धार और चूड़धार से नौराधार रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छैला बाइपास यशवंत नगर सड़क को एनएच घोषित किया जाएगा।

ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने विश्व बैंक से वित्त पोषित 1134 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना में अनियमितताओं का मामला भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने विभाग से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कुलदीप राठौर ने क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के निर्माण में तेजी लाने, सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने व नारकंडा से हाटू तक रोपवे का प्रस्ताव किया।

शिमला से विधायक हरीश जनारथा ने शहर में पार्किंग, ट्रैफिक जाम की समस्या और इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन का मुद्दा उठाया। उन्होंने शिमला के स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा का आग्रह भी किया। उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा शिमला शहर में नशा निवारण केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया।

रामपुर से विधायक नंद लाल ने अपने क्षेत्र में सड़क सम्पर्क को बेहतर बनाने, पार्किंग निर्माण और शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने रामपुर शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत पुल का निर्माण करने की बात कही। उन्होंने सेब बागवानों और किसानों की सुविधा के लिए क्षेत्र में सीए स्टोर बनाने, सराहन में रोपवे और खनेरी में ट्रामा सेंटर का भवन का निर्माण तेज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में नशे की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

जिला लाहौल–स्पिति

लाहौल–स्पिति से विधायक रवि ठाकुर ने क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थाई समाधान करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में अल्सर और कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अध्ययन करवाने की बात कही। रवि ठाकुर ने उदयपुर बहुतकनीकी महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया और पशु पालन विभाग में रिक्त पद भरने, क्षेत्र में चार स्थानों पर रोपवे लगाने और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव भी किया।

बैठक में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासू सूद सहित समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संबंधित उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक निशा कुमारी द्वारा क्वालिटी प्रिन्टर, निर्मला निवास, वार्ड–1, राजा का बाग, अर्की, जिला सोलन से मुद्रित व गांव व डाकघर बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन से प्रकाशित। मोबाईलः 70186-84867, ईमेल पता-himachalgrameen@gmail.com